

दैनिक भास्कर

भोपाल, 3 नवंबर, 2009

आईआईएम और आईआईटी के छात्रों की जिज्ञासा

कैसे होता है सरकारी काम

राजेश माली | भोपाल

आमतौर पर कामकाज के सरकारी ढर्रे की आलोचना की जाती है, लेकिन आईटी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऊंची उड़ान का सपना संजोने वाले युवा सरकारी कार्यप्रणाली को समझने में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रदेश सरकार के विभिन्न महकमों के कामकाज का गुरु सीखने के लिए आईआईएम और आईआईटी के छात्र इतने बेकरार हैं कि इसके लिए उन्होंने बिन बुलाए ही आवेदन भेज दिए। यही नहीं अपने छात्रों के रुझान को देखते हुए आईआईएम इंदौर ने तो इंटरशिप के लिए अपने विद्यार्थियों को राज्य शासन के पास भेजने को पहली प्राथमिकता दी है।

राज्य सरकार के लिए 'थिंक टैंक' का काम करने वाले भोपाल स्थित सुशासन एवं नीति विश्लेषण



इसलिए हैं दिलचस्पी

आईआईएम इंदौर की प्लेनमेंट कमेटी के चेयरमैन प्रो. प्रशांत सलवान के अनुसार सरकारी क्षेत्र में काफी लिवेज होने जा रहा है, इसलिए प्रायवेट कंपनियों भी समझ रही हैं कि सरकारी तंत्र को समझ रखने वाले लोग भी जरूरी हैं।

स्कूल का इंटरशिप कार्यक्रम एक ही साल में इतना लोकप्रिय हो गया है कि देश के जाने-माने संस्थान भी अपने विद्यार्थी भेजने के लिए उत्सुक हैं। इसी साल अप्रैल से जुलाई के बीच हुए देश के अपनी तरह के पहले इंटरशिप कार्यक्रम में आईआईएम इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईएफएम भोपाल के 20 विद्यार्थियों ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों में दो महीने तक काम किया था।

स्कूल के महानिदेशक डॉ.एचपी दीक्षित बताते हैं पहले प्रयास को मिली अपार सफलता के बाद देश के कई संस्थानों ने अपने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए हमसे संपर्क साधा है। स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आईआईएम और आईआईटी के 35 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन भी कर दिए हैं।

शेष | पेज 10

कैसे होता है सरकारी...

इस मर्तबा इंटरशिप के लिए आईआईएम इंदौर, आईआईटी कानपुर के अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नई दिल्ली सहित अन्य संस्थानों से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया में उन विभागों के अफसरों को भी शामिल करेंगे जिनके अधीन विद्यार्थी इंटरशिप करेंगे। आगामी एक-दो दिन में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आईआईटी के विद्यार्थियों के लिए अगले साल अप्रैल से मई तथा आईआईएम के विद्यार्थियों के लिए जून से जुलाई तक इंटरशिप कार्यक्रम चलेगा। गौरतलब है सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की शुरुआत राज्य सरकार ने जनवरी 08 में की है। फरवरी 09 में राज्य मंत्रिमंडल सदस्यों के लिए हुई चिंतन बैठक के लिए पाठ्यसामग्री तैयार करने में स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा था।